

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *211
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

उद्यम स्थापित करने के लिए एमएसएमई योजनाएं

*211. श्रीमती भारती पारधी:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आम आदमी की आसान ऋण के उपयोग के माध्यम से उद्यम स्थापित करने में सहायता करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना ग्रामीण लोगों के लिए प्रभावी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश तथा आकांक्षी जिले उस्मानाबाद में इनके तहत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या एमएसएमई क्षेत्र की योजनाओं से देश में स्टार्ट-अप की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्टार्ट-अप/व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. +*211 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार आम आदमी को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए एक स्कीम है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, लाभार्थी विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

शुभारंभ से अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) तक, पीएमईजीपी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7.98 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 22,506.4 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएमईजीपी का क्षेत्र-वार कार्य-प्रदर्शन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बजट का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और उस्मानाबाद आकांक्षी जिले में संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ii) पीएम विश्वकर्मा: पीएम विश्वकर्मा स्कीम परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने हेतु समग्र स्कीम है जिसमें वे शामिल किए गए 18 व्यापारों में हाथ और औजारों का उपयोग करके कार्य करते हैं। यह स्कीम निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

- i. पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता
- ii. कौशल उन्नयन
- iii. टूल किट प्रोत्साहन
- iv. ऋण सहायता
- v. डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
- vi. विपणन सहायता

चूंकि पीएम विश्वकर्मा एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। इसके शुभारंभ के बाद से, दिनांक 10.03.2025 तक, मध्य प्रदेश राज्य से 2.67 लाख आवेदन

सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं, और स्कीम के लाभ शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त धाराशिव, महाराष्ट्र से 2,665 आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं, और स्कीम के लाभ शुरू किए गए हैं।

(घ) से (ङ): देश के स्टार्टअप पारितंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की शुरुआत की गई। 31 जनवरी, 2025 तक 1,61,150 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार तीन स्कीमों नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि सभी श्रेणियों और क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

(च): पिछले तीन वर्षों के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सृजित की गई प्रत्यक्ष-नौकरियों (स्व-रिपोर्ट) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित सृजित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का राज्य-वार कार्य-निष्पादन **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं +*211 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 - वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) से सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएमईजीपी का क्षेत्र-वार कार्य-प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	ग्रामीण			शहरी		
	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सहायता प्राप्त इकाइयों का %	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सहायता प्राप्त इकाइयों का %	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
2021-22	84,696	82%	2,585.86	18,523	18%	391.80
2022-23	68,470	80%	2,323.48	16,697	20%	398.69
2023-24	68,939	77%	2,546.19	20,179	23%	547.68
2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	32,968	81%	1,368.58	7,732	19%	237.18

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं +*211 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित मार्जिन मनी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का ब्यौरा:

वित्तीय वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.
2021-22	209.61	8,082
2022-23	181.30	5,957
2023-24	185.21	5,292

उस्मानाबाद आकांक्षी जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित मार्जिन मनी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी (रु. करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
2021-22	1.86	102
2022-23	1.82	93
2023-24	1.46	53

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं +*211 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सृजित प्रत्यक्ष-नौकरियों (स्व-रिपोर्ट) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण:

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कैलेंडर वर्ष		
	2022	2023	2024
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71	85	137
आंध्र प्रदेश	3,062	5,750	5,259
अरुणाचल प्रदेश	55	185	252
असम	2,623	3,350	3,418
बिहार	4,692	9,061	7,378
चंडीगढ़	898	1,324	875
छत्तीसगढ़	2,214	3,239	4,774
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	147	138	144
दिल्ली	31,880	38,483	29,948
गोवा	887	824	879
गुजरात	23,944	48,214	35,834
हरियाणा	13,849	26,115	23,232
हिमाचल प्रदेश	1,029	1,089	969
जम्मू एवं कश्मीर	1,306	2,437	2,164
झारखंड	1,924	3,525	3,125
कर्नाटक	24,898	35,273	28,795
केरल	10,345	11,788	10,267
लद्दाख	52	44	31
लक्षद्वीप	0	31	0
मध्य प्रदेश	11,748	12,238	10,353
महाराष्ट्र	52,143	65,199	57,505
मणिपुर	309	195	385
मेघालय	61	157	106
मिजोरम	106	79	86

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कैलेंडर वर्ष		
	2022	2023	2024
नागालैंड	71	239	3,697
ओडिशा	4,632	6,532	10,797
पुदुचेरी	237	568	213
पंजाब	2,319	4,983	3,527
राजस्थान	11,639	13,748	11,372
सिक्किम	22	8	0
तमिलनाडु	18,147	30,620	26,223
तेलंगाना	15,081	18,509	16,615
त्रिपुरा	202	193	313
उत्तर प्रदेश	23,181	33,992	34,807
उत्तराखंड	1,684	2,401	7,331
पश्चिम बंगाल	9,462	11,565	11,110
कुल	274,920	392,181	351,921

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं +*211 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानित सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	अंडमान निकोबार	1,296	968	1,080
2	आंध्र प्रदेश	19,816	24,584	44,616
3	अरुणाचल प्रदेश	1,568	1,264	1,352
4	असम	30,840	20,768	19,336
5	बिहार	19,816	35,672	54,696
6	चंडीगढ़	168	120	80
7	छत्तीसगढ़	24,160	20,344	19,032
8	दिल्ली	800	576	400
9	गोवा	696	528	544
10	गुजरात*	33144	24568	24000
11	हरियाणा	13,808	12,472	11,184
12	हिमाचल प्रदेश	10,192	7,440	7,792
13	जम्मू कश्मीर	173,184	96,184	120,520
14	झारखंड	13,712	14,808	16,808
15	कर्नाटक	47,016	44,944	37,376
16	केरल	22,312	25,032	27,112
17	लद्दाख	2,360	728	976
18	लक्षद्वीप	56	16	-
19	मध्य प्रदेश	64,656	47,656	42,336
20	महाराष्ट्र**	33024	29000	22128
21	मणिपुर	9,112	4,360	2,784
22	मेघालय	5,592	2,448	2,240
23	मिजोरम	5,200	3,296	3,208
24	नागालैंड	9,928	3,752	4,136
25	ओडिशा	34,408	31,040	23,800
26	पुदुचेरी	528	200	240
27	पंजाब	14,320	12,512	11,752
28	राजस्थान	20,792	16,296	13,424
29	सिक्किम	680	456	1,056
30	तमिलनाडु	47,776	49,120	54,512
31	तेलंगाना	23,248	20,320	20,024

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
32	त्रिपुरा	7,664	5,624	4,704
33	उत्तर प्रदेश	100,752	92,808	93,512
34	उत्तराखंड	14,688	14,424	10,832
35	पश्चिम बंगाल	18,440	17,008	15,352
	कुल	825,752	681,336	712,944

* दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित